भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 463

उत्तर देने की तारीख 25 जुलाई, 2019

3 श्रावण, 1941 (शक)

विभिन्न खेलों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम

463. श्रीमती केशरी देवी पटेलः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रयागराज (इलाहाबाद) जिले में अवस्थित भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के प्रशिक्षण केंद्र में विभिन्न खेलों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम अब तक आंरभ नहीं हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ करने हेतु बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स, हॉकी इत्यादि जैसे विभिन्न खेलों के कोचों की भर्ती कब तक किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या उपर्युक्त केंद्र के अलावा किसी नये इंडोर/आउटडोर स्टेडियम की स्थापना किये जाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा विभिन्न खेलों के विकास के लिये तथा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (इलाहाबाद) जिले में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु विगत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

विभिन्न खेलों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में श्रीमती केशरी देवी पटेल, माननीय संसद सदस्य द्वारा दिनांक 25.07.2019 के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 463 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख): इलाहाबाद में आवासीय आधार पर भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी) शुरू करने का निर्णय 18.01.2001 को लिया गया। यह एसटीसी शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि राज्य सरकार ने इसके संचालन के लिए खेल अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई। इस केंद्र को वित्तीय वर्ष 2006-07 से 31 जुलाई, 2017 तक एक डे-बोर्डिंग केंद्र के रूप में कार्यशील किया गया। इस केंद्र को पुन: 11 अप्रैल, 2018 को डे-बोर्डिंग केंद्र के रूप में शुरू किया गया और 07 जनवरी, 2019 को एक बैडमिंटन कोच की तैनाती की गई। राज्य सरकार द्वारा खेल अवसंरचना की अनियमित उपलब्धता का मुद्दा, जिसके कारण एसटीसी के सुगम प्रचालन में रुकावट आ रही है, पर राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

(ग) खेल राज्य का विषय होने के कारण नए इंडोर/ आउटडोर स्टेडियम की स्थापना सहित खेलों के संवर्धन का उत्तरदायित्व मुख्यत: राज्य सरकार का है। केंद्रीय सरकार खेल अवसंरचना की कमियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की पूर्ति करती है। केंद्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य के लिए 25 खेल अवसंरचनाएं संस्वीकृत की हैं। निधि को आगे जारी करना इन परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति तथा पहले जारी की गई निधि के उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति पर निर्भर करता है।

(घ) केंद्रीय सरकार खेलों के विकास और खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए जिला-वार निधियां उपलब्ध नहीं कराती हैं। जिला प्रयागराज (इलाहाबाद) के खिलाड़ियों सहित सभी खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा के आधार पर खेलो इंडिया स्कीम के तहत साई प्रशिक्षण सुविधाएं और लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

****